जनसत्ता

घाटी में आतंकी

जम्मू-कश्मीर से लगती भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी नहीं हो रही हो। इससे सीमाई इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस साल पाकिस्तान ने दो हजार पचास बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। जाहिर है, पाकिस्तानी फौज भारत को उकसाने के लिए गोलीबारी, मोर्टारों से हमले और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने जैसी रणनीति पर काम कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में संघर्षविराम समझौता हुआ था और दोनों देशों ने यह तय किया था कि उकसावे के लिए कोई भी पक्ष अपनी ओर से पहले गोलीबारी नहीं करेगा। लेकिन सीमापार से होने वाली अनवरत गोलीबारी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाकिस्तान के लिए इस समझौते का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लिए संघर्षविराम समझौता एक तरह से बेमानी है। कई बार तो सीमाई इलाकों में हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि जान बचाने के लिए लोगों को गांव छोड़ने तक को मजबूर होना पड़ जाता है और सुरक्षित ठिकाने तलाशने पड़ते हैं। इस साल अब तक भारतीय सीमा में स्थित गांवों में इक्कीस लोग पाकिस्तानी फौज की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। संघर्षविराम के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए किस सीमा तक जा सकता है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सीमा पर लगातार गोलीबारी के पीछे सबसे बड़ा मकसद भारत के सैन्य बलों का ध्यान बंटा कर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाना है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज नियंत्रण रेखा और सीमा पर बनी भारतीय चौकियों को निशाना बनाए हुए है। यों भी, पाकिस्तान भारत में हर तरफ से आतंकी घुसपैठ की साजिश रचता रहा है। पिछले दिनों ही पाक अधिकृत कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा से तीस किलोमीटर पहले पाकिस्तान ने दो हजार सैनिक और पांच सौ प्रशिक्षित कमांडो तैनात किए हैं। इनकी मदद से आतंकियों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने की योजना है। समुद्र के रास्ते भी आतंकियों की भारत में घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र में भी पाकिस्तान सेना ने विशेष बलों को तैनात किया है, ताकि उस रास्ते भी भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आसान और संवेदनशील इलाका जम्मू-कश्मीर से लगती सीमा है।

भारतीय सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता की बात कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकी हैं। घाटी में करीब ढाई सौ आतंकी मौजूद हैं। सेना और पुलिस ने भी इस बात को माना है कि अकेले श्रीनगर शहर में चौबीस से ज्यादा आतंकी हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। हालांकि श्रीनगर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों और सेना के जवानों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। फिर भी इतनी कड़ी सुरक्षा में श्रीनगर के राज बाग, जवाहर नगर, लाल चौक सहित कई इलाकों में आतंकी स्थानीय लोगों और दुकानदारों को धमकाते फिर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालत और बुरी है। पुलिस और सेना के समक्ष सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राज्य में तमाम तरह की पाबंदियां लगी होने की वजह से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान कमजोर पड़े हैं। इसका आतंकी जम कर फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सिर्फ सीमा पर नहीं, घाटी में मौजूद आतंकियों के सफाए के लिए भी कारगर रणनीति बने और उस अमल हो।

कैंसर के पांव

एक समय था जब कैंसर से पीड़ित मरीजों के मामले कभी-कभार ही सुनने में आते थे और यह लोगों के चौंकने का मामला होता था। लेकिन आज अक्सर लोगों को उनके संपर्क के किसी व्यक्ति के कैंसर से पीड़ित होने और कई बार उनकी मौत तक की खबरें सुननी पड़ती हैं। जाहिर है, कैंसर के इस तरह पांव फैलाने के पीछे एक बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खानपान से लेकर समूची जीवनशैली में आए बदलाव हैं। लेकिन इस समूचे मसले पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यह जानलेवा रोग बहुत तेजी से बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। एक खबर के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग तीन लाख बच्चे इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इनमें से अठहत्तर हजार यानी करीब एक चौथाई से ज्यादा बच्चों की मौत अकेले भारत में हो जाती है। यह आंकड़ा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दहला देने के लिए काफी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का कैंसर की चपेट में आना एक बड़ी चेतावनी है कि आने वाली पीढ़ियों पर कैंसर की भयावह मार पड़ सकती है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि यह रोग खानपान और जीवनशैली की वजह से उभरता है और आमतौर पर रोग-प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने की वजह से ही किसी व्यक्ति के शरीर में घर बनाता है। तो क्या हमारे समाज में लोग अपने बच्चों के जीवन को इस जोखिम में छोड़ रहे हैं जिसमें वे इस रोग से बचाव के प्रति लापरवाही बरतें? निश्चित रूप से कैंसर के लिए वंशानुगत या अनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की खाने-पीने चीजें बच्चों की आदत में शुमार होती गई हैं, वे उनके शरीर के पोषण की स्थिति को कमजोर करती हैं और उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा संरक्षण में रहने वाला कोई भी बच्चा आसानी से किसी बीमारी और यहां तक कि कुछ स्थितियों में कैंसर जैसे घातक रोग की चपेट में आ जाता है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा समय तक भी इसका कोई कारगर और सुलभ इलाज नहीं ढूंढ़ा जा सका है। फिर भी, अगर शुरुआती दौर में कैंसर का पता चल जाता है तो ज्यादातर मामलों में उससे निजात पाई जा सकती है।

दरअसल, हमारे यहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा इस कदर कमजोर है कि कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां समय पर पहचान में नहीं आ पातीं और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की नाहक ही जान चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति निजी अस्पतालों का रुख करता भी है तो वहां का महंगा इलाज उसे लाचार बना देता है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कैंसर पीड़ित बच्चों के अस्पताल और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने की दर केवल पंद्रह फीसद है। दूसरी ओर, विकसित देशों में कैंसर से पीड़ित अस्सी फीसद बच्चे इस रोग के इलाज के दौरान ठीक हो जाते हैं, जबकि भारत में डॉक्टर कैंसर से पीड़ित केवल तीस फीसद बच्चे ही बचा पाते हैं। जाहिर है, परिवारों में बच्चों के खानपान, जीवनशैली में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के समांतर गरीबी और जागरूकता के अभाव को दूर किए बिना इस रोक की मारक क्षमता से लड़ पाना मुश्किल बना रहेगा। सवाल है कि जब कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से इस रोग की समय पर पहचान कर पाना ही मुश्किल बना हुआ है, तब उसके इलाज को लेकर कितना आश्वस्त हुआ जा सकता है!

कल्पमेधा

हमारा कर्तव्य है कि अपने शरीर को स्वस्थ
रखें अन्यथा हम अपने मन को सक्षम
और शुद्ध नहीं रख पाएंगे।
-गौतम बुद्ध

खतरों से सफलता के सेनापति नरेंद्र मोदी

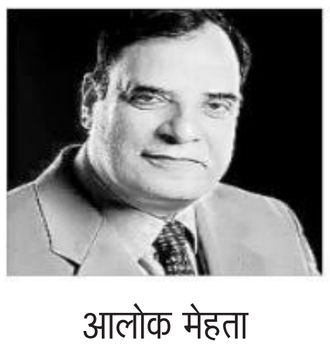

आलोक मेहता

सत्ता, संपन्नता, शिखर-सफलता से अधिक महत्त्वपूर्ण है- संघर्ष की क्षमता और जीवन मूल्यों की दृढ़ता। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री पद और राजनीतिक सफलताओं के विश्लेषण से अधिक महत्ता उनकी संघर्ष यात्रा और हर पड़ाव पर विजय की चर्चा करना मुझे श्रेयस्कर लगता है। राजधानी में संभवतः ऐसे बहुत कम पत्रकार होंगे, जो 1972 से 1976 के दौरान गुजरात में संवाददाता के रूप में रह कर आए हों। इसलिए मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। हिंदुस्तान समाचार के संवाददाता के रूप में मुझे 1973-76 के दौरान कांग्रेस के एक अधिवेशन, फिर चिमन भाई पटेल के विरुद्ध हुए गुजरात छात्र आंदोलन और 1975 में इमरजंसी रहते हुए लगभग आठ महीने अमदाबाद में पूर्णकालिक रह कर काम करने का अवसर मिला था। इमरजंसी के दौरान नरेंद्र मोदी भूमिगत रूप से संघ-जनसंघ और विरोधी नेताओं के बीच संपर्क और सरकार के दमन संबंधी समाचार-विचार की सामग्री गोपनीय रूप से पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन दिनों तो उनसे भेंट नहीं हो सकी। लेकिन संयोग से नरेंद्र भाई के अनुज पंकज मोदी भी हिंदुस्तान समाचार कार्यालय में काम कर रहे थे। पंकज भाई और ब्यूरो प्रमुख भूपत पारिख से इस परिवार और नरेंद्र भाई के संघ तथा समाज सेवा के प्रति गहरी निष्ठा और लेखन क्षमता की जानकारियां मिलीं।

प्रारंभिक दौर में वहां इमरजंसी का दबाव अधिक नहीं दिख रहा था। गुजरात समाचार और संदेश जैसे अखबार 'सेंसर' की छाया में निकल रहे थे। यहां तक कि संघ से जुड़ी 'साधना' पत्रिका भी छप रही थी। एजेंसी से वैसे भी कोई सरकार विरोधी खबरें नहीं जाती थीं। इसलिए प्रतिदिन सरकार द्वारा निर्धारित समय पर अमदाबाद से जाने-आने वाली मिनी बस से गांधीनगर की यात्रा के दौरान और फिर पत्रकार-कक्षों और दफ्तरों में गुजरात की राजनीति, इमरजंसी, सेंसर, भूमिगत नेताओं की पुष्ट-अपुष्ट सूचनाएं मिलती रहीं। उन्हीं दिनों 'साधना' के संपादक विष्णु पंड्याजी से भी उनके दफ्तर में जाकर राजनीति तथा साहित्य पर चर्चा के अवसर मिले। बाद में विष्णु पंड्या के अलावा नरेंद्र मोदी ने इमरजंसी पर गुजराती में पुस्तक भी लिखी। इसलिए यह कहने का अधिकारी हूं कि सुरक्षित जेल की अपेक्षा गुपचुप वेशभूषा बदल कर इमरजंसी और सरकार के विरुद्ध संघर्ष की गतिविधियां चलाने में नरेंद्र मोदी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तारी से पहले सोशलिस्ट जार्ज फर्नांडीज भी भेस बदल कर गुजरात पहुंच थे और नरेंद्र भाई से सहायता ली थी। मूलतः कांग्रेसी, लेकिन इमरजंसी विरोधी रवींद्र वर्मा जैसे अन्य दलों के नेता भी उनके संपर्क से काम कर रहे थे। संघर्ष के इस दौर ने संभवतः नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति की कंटीली-पथरीली सीढ़ियों पर आगे बढ़ना सिखा दिया। लक्ष्य भले ही सत्ता न रहा हो, लेकिन कठिन से कठिन स्थितियों में समाज और राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प उनके जीवन में देखने को मिलता है।

इस संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण हाल में जम्मू-कश्मीर के लिए बनी अस्थायी व्यवस्था की धारा 370 की दीवार को सरकार और संसद के फैसले से ध्वस्त कर लोकतांत्रिक इतिहास का नया अध्याय नरेंद्र मोदी और उनके निकटस्थ साथी अमित शाह ने लिख दिया। सामान्यतः लोगों को गलतफहमी है कि मोदी को यह विचार तात्कालिक राजनीतिक-आर्थिक स्थितियों के कारण आया। वे 1995-96 से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ जम्मू-कश्मीर में संगठन को सक्रिय करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ जुट गए थे। चर्चा के दौरान भी जम्मू-कश्मीर अधिक केंद्रित होता था, क्योंकि भाजपा को वहां राजनीतिक जमीन तैयार करनी थी। संघ में रहते हुए भी वे जम्मू-कश्मीर की यात्राएं करते रहे थे। लेकिन नब्बे के दशक में आतंकवाद चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान कश्मीर के छत्तीसिंगपुरा में आतंकवादियों ने छत्तीस सिखों की नृशंस हत्या कर दी थी। प्रदेश प्रभारी के नाते मोदी तत्काल कश्मीर रवाना हो गए। बिना किसी सुरक्षाकर्मी या पुलिस सहायता के वे सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए। तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब पता लगा तो उन्होंने फोन कर जानना चाहा कि 'आप वहां कैसे पहुंच गए। आतंकवादियों द्वारा यहां-वहां रास्तों में भी बारूद बिछाए जाने की सूचना है। आपके खतरा मोल लेने से मैं स्वयं मुश्किल में पड़ जाऊंगा।' यही नहीं, उन्होंने पार्टी प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी से शिकायत की कि आपका यह सहयोगी बिना बताए सुरक्षा के बिना घूम रहा है। तब आडवाणीजी ने भी मोदी को फोन किया, लेकिन मोदी ने कहा कि मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद ही वापस आऊंगा। असल में सबको उनका जवाब होता था कि अपना कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे जीवन-मृत्यु की परवाह नहीं होती। जम्मू-कश्मीर के दुर्गम इलाकों और गांवों में यात्राओं के कारण वे जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को समझते हुए उसे भारत के सुखी-संपन्न प्रदेशों की तरह विकसित करने का संकल्प संजोए हुए थे। लेह-लद्दाख में जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से विचलित हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी को कोई समस्या नहीं होती। तिब्बत, मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा भी वे 2001 से पहले कर आए थे। तभी उन्होंने यह सपना भी देखा था कि कभी लेह के रास्ते हजारों भारतीय कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। उम्मीद की जाए कि लद्दाख और कश्मीर आने वाले वर्षों में स्विजरलैंड से अधिक सुगम,

आकर्षक और सुविधा संपन्न हो जाएगा।

हिमालय की तरह नर्मदा भी उनके दिल से जुड़ी है। उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर की पृष्ठभूमि के कारण मैं 1973-74 से नर्मदा के पानी बंटवारे, राजनीतिक विवाद तथा इसके पौराणिक महत्त्व के साथ ही आधुनिक प्रगति में नर्मदा की जल-शक्ति के उपयोग पर लिखता रहा हूं। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी से नर्मदा पर बातचीत के अवसर मिले। दो साल पहले शुभि पब्लिकेशंस के संजय आर्य ने चर्चा के दौरान माना कि राजनीतिक विवादों से हट कर नर्मदा के महत्त्व पर अंग्रेजी में कोई पुस्तक नहीं है। मैंने लिखना स्वीकार किया। इस पर भव्य चित्रों के साथ काफी टेबल बुक बनने की तैयारी हुई। मैंने नरेंद्र मोदी को पुस्तक के लिए लिखने का संदेश भेजा। फिर पांडुलिपि भिजवाई, तो उन्होंने व्यस्तताओं के बावजूद एक सुंदर लिखित टिप्पणी भेज दी। पुस्तक छपने के बाद प्रकाशक के साथ उनसे भेंट हुई तो नर्मदा-हिमालय पर बातों में वे तल्लीन हो गए। बहरहाल, असली खुशी हम दोनों के लिए यह रही कि विवादों से हट कर पचास वर्षों से लटका नर्मदा सरदार सरोवर बांध का निर्माण पूरा होने के बाद लाखों किसानों को खेती और गांवों को पीने का पानी भी पहुंच रहा है। इंदौर को नर्मदा का पानी पाने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ा था। उज्जैन को भी हाल के वर्षों में नर्मदा का पानी मिलने लगा।

नरेंद्र मोदी भारत के ही नहीं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में अग्रणी समझे जाने लगे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अंतरिक्ष, मंगल, चंद्रयान की सफलताओं से अधिक गांवों को पानी, बिजली, बेटियों को शिक्षा, गरीब परिवारों के लिए मकान, शौचालय और घरेलू गैस उपलब्ध कराने के अभियानों से अधिक संतोष मिलता है। इसलिए मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि गुजरात में हुए औद्योगिक विकास और संपन्नता को ध्यान में रख कर पहले उन्होंने उद्योगपतियों को महत्त्व दिया और 'सूट-बूट की सरकार' के आरोप लगने पर एजेंडा बदल कर गांवों की ओर ध्यान दिया। फिर गरीबों की चिंता क्या किसी राजनीतिक दल और विचारधारा तक सीमित रहती है? यूरोप या अमेरिका में 1990 से पहले भी अश्वेतों और हिस्पेनिक समुदाय की कई बस्तियों और लोगों की हालत बेहद खराब थी। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में भी धीरे-धीरे स्थिति बदली और वर्षों बाद बराक ओबामा वहां राष्ट्रपति तक बने। अश्वेतों में नया विश्वास पैदा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के विचार दर्शन का आधार ज्ञान शक्ति, जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जन शक्ति और रक्षा शक्ति है। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उन्हें अमेरिका सहित कुछ देशों की यात्रा के अवसर मिले थे। इसलिए भारत की ग्राम पंचायतों से लेकर दूर देशों में बैठे प्रवासी भारतीयों को अपने कार्यक्रमों, योजनाओं से जोड़ने में उन्हें सुविधा रहती है। योग, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक मुक्ति, स्वस्थ भारत जैसे अभियान सही अर्थों में भारत को शक्तिशाली और संपन्न बना सकते हैं। आतंकवाद से निपटने का रचनात्मक रास्ता भी सामाजिक-आर्थिक विकास है। इसलिए राजनीति, विवाद, चुनौतियों से हट कर जननेता के रूप में नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्पों और सपनों के लिए शुभ कामनाएं दी जानी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रतिभा के मंच

मोनिका शर्मा

पिछले दिनों सोशल मीडिया में खूब प्रचारित हुए एक वीडियो ने भीख मांगने वाली एक महिला का जीवन बदल दिया। कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली इस महिला का किसी शख्स ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया की दुनिया में प्रसारित कर दिया। इसके बाद लाखों लोगों द्वारा साझा किए गए इस वीडियो को देख कर मुंबई से एक संगीत कंपनी कोलकाता पहुंची और उसने उसके गानों का एल्बम बनाने के बारे में सोचा। सोशल मीडिया में ही बदली और निखरी छवि में लोगों को दिख रही यह महिला अब फिल्मी दुनिया के जाने-माने संगीतकार के साथ अपने गाने रिकॉर्ड कर रही है। इतना ही नहीं, वीडियो में अपनी मां को पहचान कर उस महिला की दस साल पहले खोई बेटी भी वापस मिल गई।

यह अकेला मामला नहीं है जब सोशल मीडिया के ऐसे सकारात्मक और सार्थक इस्तेमाल की बानगी सामने आई है। इस मायावी दुनिया के जरिए कभी किसी परिवार से बिछड़े बच्चे को मिलवाने की तो कभी किसी प्रतिभा को मंच दिलवाने की खबरें भी कभी-कभार आती रहती हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र का एक किसान भी 'बालीराजा' नाम से वाट्सऐप ग्रुप बना कर चर्चा में आया था। इस समूह में उनके साथ महाराष्ट्र के अलावा, हरियाणा, पंजाब, ओडीशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान भी जुड़े हैं। इस ग्रुप के जरिए खेती-किसानी से जुड़ी नई तकनीकों और जानकारियों का लाभ किसानों को मिल रहा है। देखने में आ रहा है कि साहित्य से जुड़े संवाद से लेकर गृहिणियों की रोजमर्रा की समस्याओं तक के लिए फेसबुक और वाट्सऐप जैसे आभासी मंचों पर कई समूह बने हुए हैं, जहां सकारात्मक संवाद होता है। अपने अनुभव साझा कर एक-दूसरे को मार्गदर्शन दिया जाता है। अपने-आप तक सिमटे कितने ही लोगों का हुनर देश ही नहीं, दुनिया तक पहुंचता है।

दुनिया मेरे आगे

हालांकि आजाद अभिव्यक्ति के नाम पर हर सीमा को पार कर कुछ भी कहने की प्रवृत्ति भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में ही देखने को मिल रही है। कभी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के रूप में अस्तित्व में आए ये साझा मंच आज अराजक चरित्र वाले माध्यम बन गए हैं। इसके चलते अभिव्यक्ति अब कोलाहल बन रही है। दुनिया से जोड़ने वाला यह माध्यम अपनों से ही दूर कर रहा है। तकनीक जीवन को सुविधाजनक और सरल बनाने के ही लिए है। यह सुविधा अब हमारी मुट्ठी में है। ऐसे में सूचनाओं को साझा करने और अपने विचार रखने की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले इन साधनों को इस्तेमाल करने का तरीका इनके सदुपयोग या दुरुपयोग को तय करता है। तकनीक के साथ भी स्याह और उजला, दोनों ही पहलू जुड़े हुए हैं। इसे सनक बना लेने के खामियाजे भी हैं और आत्मनियंत्रण के साथ सदुपयोग करने के सकारात्मक परिणाम भी।

दरअसल, सोशल मीडिया ने इस संसार के लिए 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को हकीकत बना दिया है। क्लिक भर में खबरें, तस्वीरें और जानकारियां दुनिया भर में पहुंच जाती हैं। कमोबेश हर आभासी मंच के जरिए हजारों भ्रामक वीडियो आए दिन लोगों तक पहुंचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दुनिया के बाईस देशों में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक चौंसठ फीसदी भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सत्तावन प्रतिशत है। अफसोस कि यह समस्या और बढ़ रही है। नतीजतन, हमारे यहां सोशल मीडिया की वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं और अकेलापन भी। ऐसे में इन मंचों का सकारात्मक इस्तेमाल एक नई उम्मीद जगाता है।

दुखद है कि हाल के वर्षों में सोशल मीडिया केवल फर्जी समाचार फैलाने, द्वेष भरी टिप्पणियां करने और किसी की छवि बिगाड़ने के लिए ही सुर्खियों में आया। यहां साझा की जाने वाली चीजों के साथ एक उन्माद भी जुड़ गया, जिसके चलते न किसी की निजता का मान करने की सोची जा रही और न ही अफवाहें फैलाने में कोई हिचक है। इसीलिए खुद की जिंदगी से जुड़ा कोई पहलू हो या औरों से संबंधित कोई सूचना, उसे फैला देना एक शगल बन गया। कभी भीड़ को कातिल बनातीं अफवाहें तो कभी फर्जी तस्वीरों से किसी चर्चित चेहरे की छवि बिगाड़ना। कभी किसी जीते-जागते सितारे की मौत की खबर फैला देना तो कभी विचार साझा करने के मंचों पर महिलाओं को ट्रोल किया जाना।

सोशल मीडिया ऐसी सामग्री का अड्डा बन रहा है, जहां फैली नकारात्मक खबरें समाज में खून-खराबे का कारण तक बन रही हैं। वाट्सऐप पर फैली बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते कई लोगों की जान ले ली गई। अफसोस कि आभासी दुनिया में फैली ऐसी अफवाहों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसे में गिनती की सही, पर ऐसी खबरें वाकई सुकूनदायी हैं कि इन आभासी मंचों के जरिए बेहतरी लाने वाले प्रयास भी किए जा सकते हैं। एक वायरल वीडियो किसी का जीवन संवार दे सकता है। दूरदराज के गांवों में बैठे किसान कृषि से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कोई गृहिणी अपने घर से काम करते हुए उसका प्रचार-प्रसार कर सकती है, किसी की प्रतिभा को पहचान मिल सकती है।

सेहत की सुध

समृद्ध भारत का सपना स्वस्थ भारत की आंखों से ही देखा जा सकता है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग और सक्रिय करके ही देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार 2016 में दुनिया में बीमारियों से 96 लाख लोगों की जान चली गई। इनमें 63 फीसद मौतें गैर-संक्रामक रोगों से हुईं। गैर-संक्रामक बीमारियों से मरने वालों में 33 लाख पुरुष और 27 लाख महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में जिन बीमारियों से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं उन पर शारीरिक सक्रियता, व्यायाम, योग आदि से काबू पाया जा सकता है।

डब्ल्यूटीओ के मुताबिक पौष्टिक भोजन, तंबाकू से दूरी और शारीरिक सक्रियता से दिल की गंभीर बीमारियों और टाइप-2 मधुमेह से होने वाली असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। साथ ही अन्य बीमारियों से होने वाली 40 फीसद मौतों को टाला भी जा सकता है। यदि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे भारी खर्च में कमी आएगी और वह अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर सकेगी।

आंकड़ों के हिसाब से यदि भारत के लोग स्वस्थ हो जाएं तो भारत की जीडीपी में 1.4 फीसद का इजाफा किया जा सकता है। आज देश में ज्यादातर परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का मुख्य कारण बीमारियों पर किया गया भारी भरकम खर्च है। लिहाजा यह आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी अभियान चलाएं जाएं। सरकार ने इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की है जो उसकी स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को बताता है। इसके तहत संपूर्ण देश में स्वास्थ्य जागरूकता व खेलकूद जैसी गतिविधियों में लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में खेल मंत्रालय के साथ-साथ पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका अहम होगी। यह अभियान चार वर्षों तक चलेगा जिसमें भोजन की आदत, खेल कूद, रोग निवारण के उपाय और तंदुरुस्ती पर बल दिया जाएगा। उम्मीद है कि सरकारी तंत्र इस अभियान को रस्मअदायगी की तरह नहीं लेगा और इसे सफल बनाने के लिए हर देशवासी की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

● ***शशांक मिश्रा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश***

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बदहाल किसान

सरकार किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात करती है वहीं नीति आयोग के मुताबिक 2011-12 से लेकर 2016-17 तक किसानों की आमदनी 0.44 फीसद प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ी है। 2017-18 में यह शून्य फीसद और 2018-19 में तो शून्य से नीचे चली गई है। जब तक किसानों की आमदनी तय करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक किसानों की आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं हैं।

● ***सुरज कुमार, प्रजापति मोहल्ला, पटना***

सामूहिक जिम्मेदारी

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो ताजा जीवन अनुकूलता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है उसमें न केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बल्कि देश की व्यावसायिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई भी नीचे फिसल गई है। दिल्ली रहने के लिए दुनिया के शहरों में 112 से 118 में स्थान पर आ गई है। भारत एक विकासशील देश है। हमें ऐसे शहर चाहिए जो दुनिया को भारत आने के लिए मजबूर करें। जब हम शहरों को रहने लायक बनाएंगे तो ज्यादा निवेश और खुशी को सहजता से आमंत्रित कर सकेंगे।

हमारे शहर लगातार विस्थापन और पुनर्वास से गुजर रहे हैं। यहां स्थिरता न के बराबर है। न हमें इनकी संस्कृति की चिंता है और न परिवेश की। लोग यहां खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी बड़ी आबादी ऐसी है जो मूलभूत चिकित्सा सेवाओं से भी वंचित है। सड़क, बिजली, पानी के मोर्चे पर भी समस्याएं जितनी सुलझाई जाती हैं उससे ज्यादा उलझी नजर आती हैं। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो उचित शिक्षा से वंचित हैं। निस्संदेह, हमें वियना, सिडनी, ओसाका, टोरंटो, टोक्यो से सीखना चाहिए। ऑस्ट्रिया के शानदार शहर वियना ने जीवन अनुकूलता सूचकांक में अपने सर्वोच्च स्थान को कायम रखा है। इन शहरों ने रहवास के ऊंचे मुकामों को कैसे हासिल किया है, हमें इनकी कामयाबी का अध्ययन करना चाहिए।

यह एक ऐसा मोर्चा है जहां जिम्मेदारी सामूहिक है। शहरों को रहने लायक बनाने के लिए जहां शासन-प्रशासन के स्तर पर एकजुट होकर समेकित विकास के लिए काम करना होगा वहीं नागरिकों को भी देखना होगा कि शहर को रहने लायक बनाने में उनका कैसा और कितना योगदान हो सकता है। यह भी तय करना होगा कि यहां से हमें और नीचे गिरना है या फिर ऐसे ठोस कदम उठाने हैं जिनसे अगले वर्ष की रैंकिंग में हमारी स्थिति बेहतर हो जाए।

● ***सौरभ शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़***

उन्माद के विरुद्ध

भीड़ द्वारा किसी को घेर कर मार दिया जाना यानी मॉब-लिचिंग किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है चाहे उसके लिए कितने भी कुतर्क गढ़ लिए जाएं। दरअसल, कोई भी समुदाय किसी पर प्रभुत्व तभी हासिल करना चाहता है जब वह असुरक्षा की भावना से पीड़ित हो। यह बुनियादी कारण है किसी भी हत्यारी भीड़ के मनोविज्ञान का। दूसरा कारण है बंद दरवाजों से आता बेशर्म राजनीतिक समर्थन जिसने इन खूंखार मंसूबों को 'कुछ नहीं होगा' के लबादे में ढांप दिया है। इस तरह घटनाओं की एक खास अंतराल के बाद पुनरावृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है कानून एवं न्यायपालिका द्वारा कोई नजीर न मिलना।

अलवर के पहलू खान की हत्या के आरोपी सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए। यह अपराधियों को साहस देता है। मॉब-लिचिंग रोकने के लिए ऐसी घटनाओं पर त्वरित लेकिन निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो ताकि इनकी पुनरावृत्ति रुके और बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर ऐसी चीजों पर मुखरता से बात रखनी होगी। हर पाले को अपनी विचारधारा और अपने लोगों को बचाने की कोशिश छोड़नी होगी। याद रखिए 'लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में...!'

● ***दीपक तैनगुरिया, दिल्ली विश्वविद्यालय***